

मत भागों
लोगों के पीछे
जिन्हें तुम्हारी कोई
परवाह ही नहीं।
- अज्ञात



विनाशकारी कदम का नतीजा

दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कल से इस पूरे साल मानव समाज जितने भी ईंधन, पेयजल, कपड़ा, अनाज, मांस-मछली-अंडा वगैरह का उपभोग करेगा, उन्हें अपनी सहज गति में उपजाने की क्षमता पृथ्वी में नहीं है।

अनिल शर्मा।

'अर्थ ओवरशूट डे' बोले तो साल का वह दिन जब हम धरती द्वारा पूरे साल के लिए उपलब्ध कराए गए समस्त संसाधनों का उपभोग कर चुके होते हैं। साल भर के लिए उपलब्ध कराए गए संसाधन से मतलब संसाधनों की उस मात्रा से होता है जिसका पृथ्वी एक साल में पुनर्सृजन कर सकती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कल से इस पूरे साल मानव समाज जितने भी ईंधन, पेयजल, कपड़ा, अनाज, मांस-मछली-अंडा वगैरह का उपभोग करेगा, उन्हें अपनी सहज गति में उपजाने की क्षमता पृथ्वी में नहीं है।

ऐसे में इन्हें इस ग्रह के संचित कोष से हासिल किया जाएगा, जो अगले दस-बीस या सौ साल में खत्म हो जाएगा। यह ऐसे ही है जैसे पूरे महीने के लिए निर्धारित

अपना बजट हम 20 दिन में ही उड़ा सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं चल सकता। अर्थ ओवरशूट डे हर साल अलग-अलग तारीख को आता है। इसे निर्धारित करने का काम अंतरराष्ट्रीय थिंक टैंक ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क से जुड़े रिसर्चर्स करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस साल यह दिन पिछले साल के मुकाबले 24 दिन देर से आया है। पिछले साल यह 29 जुलाई को ही आ गया था। 1970 के दशक से ही अर्थ ओवरशूट डे साल-दर-साल पीछे की ओर ही खिसकता आ रहा है। इस साल इसके आगे बढ़ने का जो दुर्लभ संयोग दिख रहा है, वह भी कोई राहत नहीं दे रहा। वजह यह है कि इसके पीछे कोरोना



वायरस से उपजी महामारी है। यानी यह मानव समाज के विवेकशील प्रयासों का परिणाम नहीं बल्कि कूदरत के एक विनाशकारी कदम का नतीजा है। वायरस जनित महामारी और उससे बचने के लिए लॉकडाउन जैसे मजबूरी में अपनाए गए उपाय से मनुष्य समाज पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े। इनके साइड इफेक्ट के रूप में अगर थोड़ा फायदा यह हुआ कि प्रकृति के संसाधनों की खपत में कुछ कमी आ गई तो इस पर खुश नहीं हुआ जा सकता। कारण यह कि एक तो इसकी बेहिसाब कीमत चुकानी पड़ी, दूसरे यह कोई स्थायी उपलब्धि नहीं है।

जैसे ही कोरोना का प्रकोप कम होगा और जीवन अपनी पुरानी लय में लौटेगा, वैसे ही प्राकृतिक संसाधनों की अंधाधुंध खपत फिर शुरू हो जाएगी। साफ है कि धरती के संसाधनों को बचाने का काम कोविड-19 जैसी प्राकृतिक आपदाओं के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। हां, हम इससे सबक जरूर ले सकते हैं। दुनिया भर की सरकारों में बैठे नीति नियंताओं ने कोरोना के दबाव में आर्थिक विकास की लगातार तेज होती गाड़ी पर इमरजेंसी ब्रेक लगाया, जिसके झटके ने सब उथल-पुथल कर दिया। सवाल है कि स्पीड कम करने का यही काम सोचे-समझे ढंग से क्यों नहीं हो सकता? कुछ इस तरह कि पृथ्वी का भविष्य सुरक्षित रहे और किसी को बड़ा झटका भी न लगे।

प्रसन्न

अशोक बोहरा। जीवन में सदा खुश या प्रसन्न चित्त रहना जरूरी है। कई ऐसे लोग हैं जो दिनभर उदास रहते हैं और बहुत से हमेशा सबकुछ होने के बाद भी दुखी रहते हैं। खुश रहने के लिए हम जीवनभर प्रयास करते हैं। कुछ चीजों को लेकर हम यह सोचते हैं कि अगर वो मिल जाए तो हमें सच्ची खुशी मिल जाएगी, लेकिन हम इस मामले में गलत साबित होते हैं। कई बार तो हम बेवजह ही बनावटी सुख के लिए अन्य सच्ची खुशियों को नजरअंदाज भी कर देते हैं। हमारी असीमित इच्छाएं छोटी-छोटी खुशियों को भी हमसे दूर कर देती हैं। हमने 10 बातें धार्मिक पुस्तकों से संकलित की हैं और 5 बातें अन्य पुस्तकों से। सभी बातों को आधुनिक दृष्टिकोण अपनाते हुए लिखा गया है। बहुत से लोग व्यर्थ की इच्छाएं भी पाल लेते हैं जोकि सही नहीं होती।

धर्म-दर्शन



संपादकीय

आत्मनिर्भर तंत्र

'वोकल फॉर लोकल' अभियान में उद्योगों के दायरे को बढ़ाने की क्षमता है। भारतीय कंपनियों ने तत्काल हैंड सेनिटाइजर, वेंटिलेटर और मास्क जैसी आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने की चुनौती का सफलता से सामना कर अपनी क्षमता को मजबूती से प्रमाणित किया है। अमूल, डार, गोदरेज, टाटा आदि भारतीय ब्रांडों को केवल भारतीय ब्रांडों के साथ जुड़ी गर्व की भावना के कारण एक विविध, बहु-स्तरीय उपभोक्ता समूह के समर्थन का लाभ नहीं होता है, बल्कि स्थानीय मीडिया, स्थानीय भाषा, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लैटफॉर्म के कारण भी लाभ होता है। भारतीय उत्पादों को गुणवत्ता, नवाचार, मूल्य निर्धारण और विपणन मिश्रण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि कॉरपोरेट टर्फ वार को जीतना एक आदत बन सके। इस अभियान की वास्तविकता काफी हद तक पूर्वापेक्षाओं पर निर्भर करती है। जैसे सूचना और विपणन नेटवर्क का निर्माण, ऋण, बुनियादी ढांचा, उपयुक्त प्रौद्योगिकी, प्रेरणा और प्रशिक्षण के साथ जेएएम ट्रिनिटी (जन धन-आधार-मोबाइल), प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) और बैंक मित्र अवधारणा जैसे उपाय भारतीय इको सिस्टम को मजबूत करने के लिए आवश्यक हैं। विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए एक 'माइंडसेट' की भी आवश्यकता होती है। इसके लिए वातावरण बनाना होगा। भू-राजनीतिक गतिशीलता, वैश्विक विकास की जटिलताओं और राष्ट्रीय आवश्यकताओं को देखते हुए सफलता के मंत्र के लिए एक आत्मनिर्भर तंत्र होना चाहिए।

कभी सोवियत संघ जैसा महाबली देश टुकड़ों में बिखर कर इतिहास के लिए एक बड़ा संदेश छोड़ता है तो कभी नेपाल जैसा छोटा देश 'मुक्ति युद्ध' की कामयाबी से उस संदेश पर पुनर्विचार की जरूरत जता देता है।

स्थानीयता का लंबा अतीत

कलराज मिश्र।।

अभूतपूर्व परिस्थितियों का समय है। कोरोना महामारी, टिड्डी हमलों, तूफानों और भूकंप के साथ-साथ 41 वर्षों में पहली बार नकारात्मक आर्थिक विकास की स्थितियों से भारत जूझ रहा है। चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा पर युद्ध की आशंका अलग बनी हुई है। इस चुनौतीपूर्ण माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए भारतीय नागरिकों से स्थानीय उत्पादों की खरीद की जो अपील की है, वह संकट में हमारा संबल है। इस 'स्थानीय' (लोकल) ने हमारी मांग को पूरा किया है, इसने हमें बचाया है। 'स्थानीय' सिर्फ जरूरत नहीं है, यह हमारी जिम्मेदारी भी है। स्थानीय उत्पादों के लिए मुखर होना न केवल भारतीय कंपनियों के उत्पाद को बल्कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत में निर्मित वस्तुओं को भी बढ़ावा देता है।

स्थानीय उत्पादकता बढ़ने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, हाइपर-लोकल मार्केट को बढ़ावा मिलेगा और समग्र रूप से विभिन्न आयामों में संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। लोकप्रिय धारणा के विपरीत, इस अवधारणा का इतिहास लंबा है। वी.डी. सावरकर ने इस संबंध में तर्क दिया था कि 'विदेशी प्रतिस्पर्धा के खिलाफ राष्ट्रीय उद्योगों की रक्षा के लिए राज्य द्वारा हर कदम



उठाया जाना चाहिए'। इसी तरह दीनदयाल उपाध्याय ने स्वदेशी को 'एकात्म मानववाद' के दर्शन का एक अभिन्न तत्व बनाया। दत्तोपंत टेंगडी के 'तीसरे तरीके' ने पूंजीवाद और साम्यवाद, दोनों के लिए एक विकल्प प्रदान किया। भारतीय स्वतंत्रता के लंबे संघर्ष में दादाभाई नौरोजी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानाडे और महात्मा गांधी जैसे दिग्गजों ने स्वदेशी आंदोलन की अगुवाई की।

इसके बाद स्वतंत्र भारत में 1948 और 1956 के औद्योगिक नीति संकल्पों ने कम पूंजी निवेश के साथ अतिरिक्त रोजगार पैदा करने में ग्रामीण उद्योगों की भूमिका पर जोर दिया। ऐतिहासिक रूप से ग्रामीण उद्योगों ने विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय निर्माण क्षमता को बढ़ाया है। राजस्थान में तिलोनिया और उर्मुल, कला रक्षा, बेरोजगार महिला समिति आदि के कार्यक्रमों की सफलता इसका उदाहरण

है। 'मेक इन इंडिया' पहल के माध्यम से पूर्व में भारत में कंपनियों के संचालन की बाधाओं को खत्म कर कंपनियों की सहायता करने का प्रयास किया गया था, जिससे अर्थव्यवस्था में विनिर्माण की हिस्सेदारी 2014 के 15 प्रतिशत के मुकाबले 2020 में बढ़कर 25 प्रतिशत हो गई। लेकिन आर्थिक मंदी और कठोर स्थानीय नियमों की दोहरी मार के कारण यह योजना अधिक सफल नहीं हुई। इससे सीख लेकर सेवा क्षेत्रों की वृद्धि और अंतर्निहित क्षेत्रीय विकास सीमाओं के कारण विनिर्माण पर नए सिरे से जोर दिए जाने की आवश्यकता है।

संपूर्ण विश्व में, विशेष रूप से विकासशील देशों में एमएसएमई विकास का इंजन रहा है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था का भी आधार है और लगभग 12 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। चूंकि एमएसएमई भारत के विनिर्माण उत्पादन में 34 प्रतिशत और भारत के निर्यात में 45 प्रतिशत योगदान देता है, इसलिए यह फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज को मजबूत कर आय असमानता को कम करने में सहायक होगा। ऑक्सफैम द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि भारत की शीर्ष 1 प्रतिशत आबादी के पास अब 73 प्रतिशत संपत्ति है, जबकि 67 करोड़ नागरिकों— जिसमें देश के आधे सबसे गरीब शामिल हैं— की संपत्ति में 2006 और 2015 के बीच केवल 1 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

सूदोक्रु नवताल-5454		* * * * *	
	2		3
	9	8	2 6 4
1		3 6	9
4	3		
	8	2	1
			8 6
4	7 5		3
3 7 5	4	1	
2		8	

सूदोक्रु नवताल-5453 का हल

■ प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं।
■ प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3x3 के वर्गों में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें।
■ पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते।
■ पहेली का केवल एक ही हल है।

अपना ब्लॉग

गेम चेंजर सिद्ध हो सकता है
मोहन। 'एक मिशन मोड' में इस प्रकार के अभियानों का लगातार संचालन करने की आवश्यकता है। सभी हितधारकों के समर्थन के साथ यह गेम चेंजर सिद्ध हो सकता है। नीतियों को कार्यरूप प्रदान करने का दायित्व साहसी उद्यमियों के प्रयासों पर निर्भर है। इस रणनीति की सफलता के लिए (अ) समय पर, पर्याप्त और कम लागत वाले लोन (ब) तकनीकी उन्नयन (स) व्यापक रूप से बेहतर अवसरचतानात्मक सुविधाएं और (द) मांग की पहचान, कौशल और क्षमताओं के उन्नयन, स्थानीय संसाधनों के इष्टतम उपयोग, बाजार अनुसंधान, अंतर-संस्थागत तालमेल, प्रतिबद्ध एनजीओ एवं उद्योग संघ, अच्छे सलाहकार और सेवा प्रदाता आदि के माध्यम से बाजार में व्यवसाय के उन्नयन के लिए एक प्रणालीगत व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है। विभिन्न उत्पादों के लिए विभिन्न स्थानों पर क्लस्टर बनाए जा सकते हैं और अनुभव के आधार पर विकास मॉडल को अन्य समूहों में दोहराया जा सकता है।

